VAJIRAO & REDDY INSTITUTE
India's Top Potential Training Institute for IAS
+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

TODAY'S ANALYSIS

(आज का विश्लेषण)

(12 February 2025)

Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

Important News:

- AI के लिए भारत का दृष्टिकोण: AI एक्शन समिट में प्रधानमंत्री का संबोधन
- मणिपुर में शासन के लिए विकल्पों में से एक 'राष्ट्रपति शासन', से जुड़े संबैधनिक प्रावधान और इसका इतिहास
- संविधान में वर्णित लघु चित्रों को हटाने से जुड़ा विवाद
- MCQ

ADDRESS:
19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)

AI के लिए भारत का दृष्टिकोण: AI एक्शन समिट में प्रधानमंत्री का संबोधन

परिचय:

- पेरिस में आयोजित AI एक्शन समिट की सह-अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने की।
- प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत में AI को ठीक से समझाने के लिए एक उदाहरण देते हुए बताया कि "अगर आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट किसी AI ऐप पर अपलोड करते हैं, तो यह सरल भाषा में, बिना किसी शब्दजाल के, यह समझा सकता है कि आपके स्वास्थ्य के लिए इसका क्या मतलब है। लेकिन, अगर आप उसी ऐप से किसी व्यक्ति को उसके बाएं हाथ से लिखते हुए दिखाने के लिए कहें, तो ऐप सबसे ज्यादा संभावना है कि किसी व्यक्ति को उसके दाएं हाथ से लिखते हुए दिखाए। क्योंकि प्रशिक्षण डेटा में यही सबसे ज्यादा होता है"।
- प्रधानमंत्री ने इस उदाहरण से दर्शाया कि AI की सकारात्मक क्षमता बिल्कुल अद्भुत है, लेकिन इसमें कई पूर्वाग्रह हैं जिनके बारे में दुनिया को सावधानी से सोचने की ज़रूरत है।

- प्रधानमंत्री मोदी ने अपने उद्घाटन भाषण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए भारत के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला, जिसमें 'जिम्मेदार शासन', 'समावेशी नवाचार' और 'वैश्विक सहयोग' पर जोर दिया गया।

वैश्विक 'AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क' की आवश्यकता:

- प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि AI दुनिया भर में गवर्नेंस, अर्थव्यवस्थाओं, सुरक्षा और समाजों को नया आकार देता है। पिछली तकनीकी प्रगति के विपरीत, AI अभूतपूर्व गति से विकसित हो रहा है, जिसके लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है।
- प्रधानमंत्री मोदी ने 'AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क' स्थापित करने के लिए सामूहिक प्रयासों का आग्रह किया जो पूर्वाग्रह, गलत सूचना और साइबर खतरों जैसे जोखिमों को संबोधित करते हुए नवाचार को बढ़ावा देते हैं।
- प्रधानमंत्री मोदी ने विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के लिए विश्वास-निर्माण तंत्र और समान AI पहुंच के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि AI गवर्नेंस का मतलब केवल जोखिमों और प्रतिद्वंद्विता का प्रबंधन करना नहीं है। यह नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक भलाई के लिए AI को लागू करने के बारे में भी है।

सामाजिक परिवर्तन और सतत विकास के लिए AI:

- प्रधानमंत्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कृषि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में क्रांति लाने की AI की क्षमता पर प्रकाश डाला, जो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने में योगदान देगा।
- उन्होंने AI से जुड़े निम्नलिखित पहलुओं का आह्वान किया:
  - ➢ पारदर्शिता और समावेशिता को बढ़ाने के लिए 'ओपन-सोर्स AI सिस्टम' की।
  - ➢ निष्पक्ष और प्रतिनिधि AI मॉडल सुनिश्चित करने के लिए 'पूर्वाग्रह-मुक्त डेटासेट' की।
  - ➢ डीपफेक और गलत सूचना जैसे AI-संचालित खतरों का मुकाबला करने के लिए 'साइबर सुरक्षा' उपायों की।
  - ➢ प्रासंगिक समाधानों के लिए 'स्थानीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के साथ AI के एकीकरण' की।
- उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी ने AI की विशाल ऊर्जा खपत के बारे में चिंताओं को भी संबोधित किया, और बिजली के उपयोग को अनुकूलित करने वाले 'टिकाऊ AI मॉडल' विकसित करने का आह्वान किया। उन्होंने इस संदर्भ में फ्रांस

के साथ एक संयुक्त पहल, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) का हवाला देते हुए स्वच्छ ऊर्जा में भारत के नेतृत्व पर भी प्रकाश डाला।

AI और रोजगार: बदलते कार्यबल के अनुकूल ढलना

- उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ने AI के कारण नौकरी के कटौती के बारे में चिंताओं को स्वीकार करते हुए, जोर देकर कहा कि "तकनीकी प्रगति काम या रोजगार को खत्म नहीं करती बल्कि इसकी प्रकृति को बदल देती है"।
- प्रधानमंत्री ने AI-संचालित भविष्य के लिए कार्यबल को तैयार करने के लिए बड़े पैमाने पर 'कौशल और पुनर्कौशल' कार्यक्रमों की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही बताया कि अपने विशाल AI प्रतिभा पूल के साथ, भारत पहले से ही डिजिटल डिवाइड को पाटने के लिए अपस्किलिंग पहलों में निवेश कर रहा है।

AI के क्षेत्र में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका:

- प्रधानमंत्री ने अपने 1.4 अरब लोगों के लिए डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) के निर्माण में भारत की सफलता को प्रदर्शित किया, जो शासन और वाणिज्य के लिए कम लागत वाला, ओपन-एक्सेस नेटवर्क प्रदान करता है। भारत का डेटा सशक्तिकरण और संरक्षण आर्किटेक्चर (DEPA) सुरक्षित और लोकतांत्रिक डेटा उपयोग सुनिश्चित करता है।

- उन्होंने 'राष्ट्रीय AI मिशन' का हवाला देते हुए 'जिम्मेदार AI' विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया, जो स्टार्टअप और शोधकर्ताओं के लिए AI को सुलभ और किफ़ायती बनाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देता है। भारत अपनी सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को दर्शाने के लिए अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) भी विकसित कर रहा है।

'सभी के लिए जिम्मेदार AI' के प्रति भारत की प्रतिबद्धता:

- अपनी G20 प्रेसीडेंसी के दौरान, भारत जिम्मेदार AI विकास पर आम सहमति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। प्रधानमंत्री ने अपनी विशेषज्ञता साझा करने के लिए भारत की तत्परता की पुष्टि की: "भारत यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार है कि AI का भविष्य सभी के लिए अच्छा हो"।
- चूंकि AI मानवता के भविष्य को आकार देता है, इसलिए प्रधानमंत्री ने AI शासन के लिए मानव-केंद्रित दृष्टिकोण का आग्रह किया, जिससे नैतिक, टिकाऊ और समावेशी विकास सुनिश्चित हो सके। भारत का दृष्टिकोण सामाजिक भलाई के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की अपनी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के साथ संरेखित है, जिससे AI दुनिया भर में प्रगति और समानता के लिए एक ताकत बन सके।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

निष्कर्ष:

- पेरिस में AI एक्शन समिट में प्रधानमंत्री के संबोधन ने वैश्विक AI नेतृत्व में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। नैतिक AI शासन, सतत नवाचार और वैश्विक सहयोग के लिए उनका आह्वान दुनिया भर के हितधारकों के साथ गूंज उठा, जिससे AI युग को आकार देने में एक प्रमुख चालक के रूप में भारत की स्थिति मजबूत हुई।

VAJIRAO & REDDY INSTITUTE
India's Top Potential Training Institute for IAS
+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

मणिपुर में शासन के लिए विकल्पों में से एक 'राष्ट्रपति शासन', से जुड़े संबैधनिक प्रावधान और इसका इतिहास:

चर्चा में क्यों है?

- 9 फरवरी को मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से एन बीरेन सिंह के इस्तीफा देने के बाद, भाजपा नेतृत्व अपने विकल्पों पर विचार कर रहा है।
- अगर पार्टी सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार नहीं ढूंढ पाती है, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है - ऐसा कुछ जिसे भाजपा टालना चाहती है, क्योंकि भाजपा सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रपति शासन के खिलाफ रही है।

राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की संवैधानिक व्यवस्था:

- संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होने से राज्य सरकार के सभी कार्य केंद्र सरकार को और राज्य विधानमंडल के कार्य संसद को उस अवधि के दौरान स्थानांतरित हो जाते हैं, जब तक कि यह लागू रहता है।
- इसका एकमात्र अपवाद उच्च न्यायालयों का कामकाज है, जो अपरिवर्तित रहता है।

ADDRESS:
19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)

राष्ट्रपति शासन लगाने की संवैधानिक प्रक्रिया:

- यह प्रक्रिया तब शुरू होती है, जब राष्ट्रपति राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त करने पर या अन्यथा संतुष्ट होते हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें राज्य की सरकार इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती।
- ऐसी स्थिति में, राष्ट्रपति एक 'उद्घोषणा' जारी करेंगे, जो दो महीने तक लागू रह सकती है। इसे आगे लागू रहने के लिए इस अवधि के समाप्त होने से पहले लोकसभा और राज्यसभा को एक प्रस्ताव के माध्यम से इसे अनुमोदित करना होगा।
- यदि अनुमोदित किया जाता है, तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा को छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है और संसद तीन साल तक के लिए छह महीने के विस्तार को मंजूरी दे सकती है।

एक साल से अधिक समय बाद नवीनीकृत करने से पहले कुछ शर्तें:

- उल्लेखनीय है कि संसद द्वारा किसी उद्घोषणा को पहली बार जारी किए जाने के एक साल से अधिक समय बाद नवीनीकृत करने से पहले कुछ शर्तों को पूरा करना होगा।

- इसके तहत राष्ट्रपति शासन का आगे विस्तार केवल तभी स्वीकृत किया जा सकता है जब देश या उस विशेष राज्य में आपातकाल घोषित कर दिया गया हो, या यदि चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि राज्य में चुनाव कराने में कठिनाइयों के कारण राष्ट्रपति शासन आवश्यक है।

भारत में राष्ट्रपति शासन का इतिहास:

- 1950 से, जब संविधान पहली बार लागू हुआ, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 134 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है।
- राष्ट्रपति शासन को सबसे ज्यादा बार मणिपुर और उत्तर प्रदेश में लगाया गया है, जहाँ 10-10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है।

सबसे ज़्यादा समय तक राष्ट्रपति शासन में रहे राज्य:

- हालांकि, ये वे राज्य (केंद्र शासित प्रदेशों सहित) नहीं हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा समय केंद्रीय नियंत्रण में बिताया है। यह विशिष्टता जम्मू और कश्मीर के पास है, उसके बाद पंजाब और पुडुचेरी का स्थान है।
- 1950 से, जम्मू और कश्मीर ने राष्ट्रपति शासन के तहत 12 साल से ज़्यादा समय बिताया है और पंजाब उसी अवधि में 10 साल से ज़्यादा समय तक केंद्रीय

नियंत्रण में रहा है। दोनों राज्यों में, यह मुख्य रूप से उग्रवादी और अलगाववादी गतिविधि और अस्थिर कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण है।

- राष्ट्रपति शासन का सबसे हालिया लागूकरण पुडुचेरी में हुआ था, जब 2021 में कांग्रेस सरकार विश्वास मत में विफल होने के कारण सत्ता खो बैठी थी। पुडुचेरी ने अपने इतिहास में राष्ट्रपति शासन के तहत 7 साल से अधिक समय बिताया है, जिसका एक बड़ा कारण यह है कि सरकारें बार-बार अंदरूनी कलह या दलबदल के कारण विधानसभा में समर्थन खोती रही हैं।

राष्ट्रपति शासन पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय: एस.आर. बोम्मई वाद

- सर्वोच्च न्यायालय ने एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) के मामले में राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति और केंद्र-राज्य संबंधों पर इसके प्रभाव की व्यापक रूप से जांच की।
- उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू करने और राज्य सरकार को बर्खास्त करने के कई उदाहरणों के बाद यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में आया।

राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की राष्ट्रपति की शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन:

- सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से माना कि अनुच्छेद 356 के तहत उद्घोषणा जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति न्यायिक

समीक्षा के अधीन है और अदालतें यह देखने के लिए निर्णय की जांच कर सकती हैं कि क्या यह अवैधता, दुर्भावना, बाहरी विचारों, शक्ति के दुरुपयोग या धोखाधड़ी से ग्रस्त है।

- हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि न्यायालय राष्ट्रपति शासन लागू करने के राष्ट्रपति के व्यक्तिपरक निर्णय की शुद्धता पर विचार नहीं कर सकता, वह यह जांच सकती है कि राष्ट्रपति को दी गई सामग्री की घोषणा के लिए प्रासंगिक थी या नहीं।

राज्य सरकारों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दिशानिर्देश:

- अपने इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दिशा-निर्देश भी बनाए हैं।
- राष्ट्रपति शासन के वैध घोषणा के बाद भी, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि केवल राज्य विधानमंडल को निलंबित किया जाएगा और राज्य सरकार के अन्य अंग तब तक काम करते रहेंगे जब तक कि लोकसभा और राज्यसभा दो महीने के भीतर इसे मंजूरी नहीं दे देते।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस मंजूरी के बिना, बर्खास्त सरकार को फिर से बहाल कर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि बोम्मई वाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद के दशकों में, देश में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के मामलों में कमी आई है।

संविधान में वर्णित लघु चित्रों को हटाने से जुड़ा विवाद:

मामला क्या है?

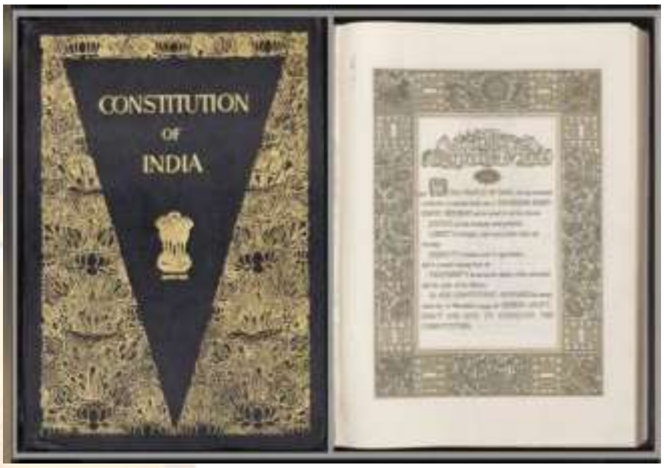

- राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ ने 11 फरवरी को कहा कि संविधान निर्माताओं द्वारा हस्ताक्षरित और संसद द्वारा किए गए संशोधनों के साथ पहली सुलेखित प्रति में 22 लघु चित्र ही एकमात्र प्रामाणिक संस्करण है जिसे पूरे देश में लागू किए जाने की आवश्यकता है और किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए।
- सभापति श्री धनखड़ ने उच्च सदन में यह बात भारतीय जनता पार्टी के सांसद राधामोहन दास अग्रवाल द्वारा देश में अब बेची जा रही संविधान की अधिकांश प्रतियों में 22 चित्र गायब होने का मुद्दा उठाए जाने के बाद कही। उन्होंने मूल चित्रों को शामिल करने की मांग की, और आरोप लगाया कि उन्हें “असंवैधानिक” रूप से हटा दिया गया था।

संविधान में वर्णित चित्रांकन की विषयवस्तु:

- उल्लेखनीय है कि संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हस्तलिखित किया था, जबकि चित्रों की परिकल्पना और क्रियान्वयन शांतिनिकेतन में कलाकार-शिक्षक नंदलाल बोस और उनकी टीम द्वारा किया गया था।
- जब संविधान में 22 हाथ से बनाई गई चित्रों को क्रम में रखा जाता है, तो उनकी कथात्मक योजना सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक भारतीय इतिहास के विभिन्न कालखंडों का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें रामायण और महाभारत के दृश्य भी शामिल हैं। इन चित्रांकन में भारत के विविध भूगोल को भी दर्शाया गया है, जिसमें रेगिस्तान में ऊंटों की सवारी से लेकर महान हिमालय तक शामिल हैं।
- इन 22 हाथ से बनाई गई चित्रों में रामायण और महाभारत के दृश्य, भगवान राम, महात्मा गांधी, अकबर, छत्रपति शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई और अन्य की तस्वीरें शामिल हैं।

संविधान में इतिहास और धर्म से लिए गए चित्रों के बारे में:

- 'भाग I: संघ और उसके क्षेत्र' में सिंधु घाटी क्षेत्र से उत्खनित बैल मुहर, संविधान में पहला सचित्र प्रतिनिधित्व है, जो दिखाई देता है।

- 'भाग II: नागरिकता' में एक आश्रम का दृश्य है जिसमें पुरुष तपस्वी आकृतियाँ ध्यानपूर्ण वातावरण में प्रार्थना कर रही हैं।
- 'भाग III: मौलिक अधिकारों' के लिए, कलाकारों ने लंका में युद्ध के बाद घर लौटते हुए भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता का रेखाचित्र बनाया गया।
- 'भाग IV: राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत', महाभारत के एक दृश्य से शुरू होता है, जिसमें युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन और कृष्ण के बीच चर्चा होती है।
- भाग V में, भगवान बुद्ध केंद्रीय आकृति हैं, जो एक शांत वातावरण में शिष्यों, जानवरों और पक्षियों से घिरे हुए हैं।
- भाग VI में, भगवान महावीर की एक छवि है, जो 24वें जैन तीर्थंकर हैं, जो ध्यान में पैर मोड़कर बैठे हैं।
- भाग XIII में, महाबलीपुरम की मूर्तियाँ और गंगा का पृथ्वी पर अवतरण देखते हैं।

भारत के विभिन्न शासकों का भी वर्णन:

- उल्लेखनीय है कि संविधान के भाग VII में सम्राट अशोक को हाथी पर बैठे हुए, बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है, भाग IX में राजा विक्रमादित्य के दरबार का एक दृश्य है, जिसमें संगीतकार और नर्तकियां हैं, जो उन्हें कला के संरक्षक के रूप में दर्शाता है।

- संविधान में प्रमुख रूप से चित्रित एकमात्र महिला आकृति, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, को संविधान के भाग XVI में मैसूर के राजा टीपू सुल्तान के साथ चित्रित किया गया है। छत्रपति शिवाजी और गुरु गोबिंद सिंह को भाग XV में दर्शाया गया है।

देश के स्वतंत्रता संग्राम की भी झांकी:

- संविधान के लघु चित्रों में महात्मा गांधी दो बार दिखाई देते हैं, दांडी मार्च का नेतृत्व करते हुए और दंगा प्रभावित नोआखली का दौरा करते हुए।
- भाग XIX में, सुभाष चंद्र बोस को एक पहाड़ी पृष्ठभूमि के सामने, झंडे को सलामी देते हुए, आज़ाद हिंद फ़ौज के सदस्यों के साथ मार्च करते हुए देखा जाता है।
- संविधान में तीन परिदृश्य नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर और उनके द्वारा रचित राष्ट्रगान को श्रद्धांजलि देते हैं, जो भारत के विविध भौगोलिक परिदृश्यों का भी जश्न मनाते हैं।

चित्र कलाकारों की नियुक्ति:

- अक्टूबर 1949 में संविधान सभा के अंतिम सत्र और 26 नवंबर, 1949 को संविधान के मसौदे पर हस्ताक्षर से ठीक पहले नंद लाल बोस को चित्रण का काम सौंपा गया था। नंद लाल बोस को संभवतः राष्ट्रवादी आंदोलन से उनके लंबे जुड़ाव

VAJIRAO & REDDY INSTITUTE
India's Top Potential Training Institute for IAS
+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

के कारण यह काम सौंपा गया था। वे महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी थे, उन्होंने 1938 में गुजरात के बारदोली के पास हरिपुरा में कांग्रेस सत्र के लिए पोस्टर डिजाइन किए थे।

ADDRESS:
19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)

MCQs

1. चर्चा में रहे 'सभी के लिए जिम्मेदार AI' के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. भारत यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार है कि AI का भविष्य सभी के लिए अच्छा हो।

2. भारत AI को दुनिया भर में प्रगति और समानता के लिए एक ताकत बनाना चाहता है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans:(c)

2. भारत में राष्ट्रपति शासन को लगाने से जुड़े इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक कुल 134 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है।

(b) राष्ट्रपति शासन को सबसे ज्यादा बार मणिपुर और उत्तर प्रदेश में लगाया गया है।

(c) जम्मू और कश्मीर ने राष्ट्रपति शासन के तहत सबसे ज़्यादा समय बिताया है।

(d) उपर्युक्त सभी सही कथन हैं।

Ans:(d)

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

3. चर्चा में रहे 'राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की संवैधानिक व्यवस्था' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन केवल राज्यपालों के सिफारिश पर ही लगाया जा सकता है।
2. राष्ट्रपति द्वारा 'उद्घोषित' राष्ट्रपति शासन के प्रस्ताव को दो महीने के भीतर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अनुमोदित करना आवश्यक होता है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans:(b)

4. भारतीय संविधान की मूल प्रति को अंग्रेजी और हिंदी में, निम्नलिखित किस व्यक्ति द्वारा हस्तलिखित किया गया था?

(a) प्रेम बिहारी नारायण रायजादा

(b) नन्दलाल बोस

(c) एच. आर. अयंगर

(d) डी. पी. खेतान

Ans:(a)

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

5. चर्चा में रहे 'संविधान मूल प्रति में जोड़े गए लघु चित्रों' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. हाथ से बनाई गई इन चित्रों की कथात्मक योजना सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक इतिहास के विभिन्न कालखंडों का प्रतिनिधित्व करती है।
2. इन चित्रों में भगवान राम, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, महात्मा गांधी, छत्रपति शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई और अन्य की तस्वीरें शामिल हैं।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

Ans:(c)